

Regarding request to start Common Service Facilities(CSC) at Railway Stations and Post Offices in the West Bengal

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमेशा अपनी जनता को पॉलिटिकल कारणों से सुविधाओं से वंचित किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने वर्ष 2020 में कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो केंद्र द्वारा चलाए जाते हैं, उनको बंद करने का डिसीजन लिया। ? (व्यवधान) आप सोचिए, कॉमन सर्विस सेंटर्स केंद्र द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से, जो साधारण लोग हैं, जो जनता है, उसको तरह-तरह की हैल्प मिलती है। जो केंद्रीय प्रकल्प हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हैल्प मिलती है। ? (व्यवधान) उसके साथ-साथ वहां से उनको आधार कार्ड के संबंध में भी हैल्प मिल सकती है।

सर, सीएससी के द्वारा और भी बहुत से काम हो सकते हैं। ? (व्यवधान) सीएससी बंद करने के कारण जो 40 हजार युवा इन सेंटर्स के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी इनसे इनकम होती थी, वे सीएससी चलाते थे, उनको पंचायत के ऑफिसों से गुंडों द्वारा धमका कर बाहर निकाल दिया गया कि आप यहां सीएससी नहीं चला सकते, आपको सीएससी बंद करना पड़ेगा। ? (व्यवधान)

ऐसी सरकार, जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती, जो सरकार अपनी जनता को प्रताड़ित करती है, उस सरकार की जनता अपने आंसू बहाती है। ? (व्यवधान) ऐसी नौबत आ गई कि उस सरकार ने यह डिसीजन लिया कि जो इकोनॉमिक सेंसेस है, वह पश्चिम बंगाल में नहीं किया जाएगा।

चेयरमैन सर, आप बताइए कि अगर इकोनॉमिक सेंसेस नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन आदमी गरीब है, कौन अमीर है? अगर इकोनॉमिक सेंसेस नहीं हुआ, तो आप लोगों को कैसे सुविधाएं देंगे? (व्यवधान) अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप गरीबों के लिए डेटा कैसे बनाएंगे? इस विषय के ऊपर, जनता की डिमांड के कारण हमने कोलकाता हाई कोर्ट में पीआईएल भी लगाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है कि आप इसके ऊपर अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार डिले कर रही है, अपना एफिडेविट भी दाखिल नहीं कर पा रही है। ? (व्यवधान) उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया गया है। ? (व्यवधान) यदि 12 तारीख तक एफिडेविट दाखिल नहीं हुआ, तो पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ? (व्यवधान)

अतः इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशंस और पोस्ट ऑफिसों में सीएससी को फिर से चालू किया जाए, ताकि पश्चिम बंगाल की जनता सीएससी से लाभ ले पाए ? (व्यवधान) पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को प्रताड़ित कर रही है। ? (व्यवधान)